

भारत में सुगम्यता उपायों को सुदृढ़ बनाना

प्रलिस के लिये:

[दवियांगजन अधिकार अधनियम, 2016](#), [सुगम्य भारत अभियान](#), [भारत का सर्वोच्च न्यायालय](#)

मेन्स के लिये:

दवियांगजनों के लिये समावेशता और समान अधिकारों को बढ़ावा देने में महत्व, सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्यों?

राजीव रतूडी बनाम भारत संघ, 2024 मामले में [भारत के सर्वोच्च न्यायालय](#) ने माना कि दवियांगजन अधिकार नयिम 2017 का उपनयिम 15, [दवियांगजन अधिकार अधनियम 2016](#) के साथ असंगत/उल्लंघनकारी है।

- न्यायालय ने कहा कि इस अधनियम द्वारा सरकार को सुगम्यता सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है लेकिन उपनयिम 15 द्वारा इसमें वविकाधीन दृष्टिकोण पर बल दिया गया है, जिससे वैधानिक प्रावधानों के बीच टकराव देखने को मलता है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने RPwD नयिम, 2017 के उपनयिम 15 को अमान्य क्यों माना?

- RPwD नयिम, 2017 का उपनयिम 15: RPwD नयिम, 2017 का उपनयिम 15, सरकारी वभिगों में सुगम्यता संबंधी दशा-नरिदेशों के लिये एक रूपरेखा प्रदान करता है, जिससे मंत्रालयों द्वारा जारी दशा-नरिदेशों को वैधानिक प्राधिकार मलता है।
- सर्वोच्च न्यायालय का अवलोकन:
 - वविकाधीन प्रकृति: [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने माना कि उपनयिम 15 से RPwD अधनियम (धारा 40, 44, 45, 46 और 89) के अनविर्य प्रावधानों का उल्लंघन होता है क्योंकि यह मंत्रालयों को बाध्यकारी दायतव के बनि सुगम्यता संबंधी दशा-नरिदेश जारी करने की अनुमतदता है।
 - अनुपालन और सामाजिक लेखा परीक्षा: दवियांगजन अधिकार अधनियम में नयिमति सामाजिक लेखा परीक्षा की आवश्यकता का प्रावधान है ताकि यह सुनिश्चित कया जा सके कि सरकारी योजनाएँ दवियांगजनों पर प्रतिकूल प्रभाव न डालें।
 - हालाँकि, RPwD नयिमों के तहत मानकीकृत दशा-नरिदेशों की कमी के कारण, इन ऑडिटों के संचालन में असंगतता रही है।
 - सुगम्यता बनाम उचित समायोजन: सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय में सुगम्यता (जसिसे सार्वजनिक अवसंरचना सुनिश्चित होती है) और उचित समायोजन (जो वशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने पर केंद्रति है) के बीच अंतर कया गया है।
 - संवैधानिक सदिधांतों के तहत मौलिक समानता प्राप्त करने के लिये दोनों ही महत्त्वपूर्ण हैं।
 - नए दशा-नरिदेशों की आवश्यकता: सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को 3 महीने के भीतर नए अनविर्य सुगम्यता दशा-नरिदेश बनाने का नरिदेश दिया, जसिमें 4 सदिधांतों पर ध्यान केंद्रति कया गया है, जसिमें सभी के लिये सार्वभौमिक डिजाइन, वभिन्न दवियांगताओं का व्यापक समावेश, स्करीन रीडर और सुलभ डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसी सहायक प्रौद्योगकियों का एकीकरण, और दवियांग वयक्तियों के साथ नरितर परामर्श शामिल हैं।

दवियांगजन अधिकार अधनियम, 2016 (RPwD अधनियम) क्या है?

- परचिय:
 - दवियांगजन अधिकार अधनियम, 2016 एक ऐसा कानून है जो दवियांगजनों को भेदभाव से बचाता है तथा उनके समान अधिकारों एवं अवसरों को बढ़ावा देता है।
 - यह अधनियम दवियांगनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCRPD) को प्रभावी बनाने के लिये बनाया गया था, जसि वर्ष 2007 में भारत द्वारा अनुमोदति कया गया था।

- **दिव्यांगजन अधिकार नियम, RPWD अधिनियम, 2016** के कार्यान्वयन के लिये प्रक्रियात्मक स्पष्टता प्रदान करने तथा उसे कार्यान्वयन करने के लिये तैयार किये गए थे।
- **भारत में दिव्यांगजन: वर्ष 2011** की जनगणना के अनुसार, लगभग **26.8 मिलियन व्यक्ति** (भारत की जनसंख्या का **2.21%**) दिव्यांग हैं।
- दिव्यांगजन: अधिनियम में दिव्यांगता को एक वकिसशील और गतशील अवधारणा के रूप में पुनरपरिभाषित किया गया है तथा दिव्यांगता की श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया, जिससे केंद्र सरकार को इसमें और श्रेणियाँ शामिल करने की अनुमति मिल गई।
- **अधिकार:**
 - **सरकारी ज़मिमेदारी:** उपयुक्त सरकारों का यह दायित्व है कि वे प्रभावी उपाय करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दिव्यांगजन (PwD) अन्य लोगों के साथ समान आधार पर अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें।
 - **वशेष लाभ:** बेंचमार्क दिव्यांगता और उच्च सहायता की आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिये प्रावधान किये गए हैं, जिनमें शामिल हैं:
 - **निःशुल्क शिक्षा:** 6 से 18 वर्ष की आयु के दिव्यांगजन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्राप्त है।
- **आरक्षण:** बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त उच्च शिक्षा में 5% आरक्षण तथा सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण का अधिकार है।
 - "बेंचमार्क दिव्यांगता" वाले व्यक्तियों की पहचान उन लोगों के रूप में की जाती है, जिन्हें नरिदृष्ट दिव्यांगता का कम-से-कम 40% प्रमाणित किया गया है।
 - **अभिम्यता:** सरकारी और नज़ी प्रतिष्ठानों सहित सार्वजनिक भवनों में नरिधारित समय सीमा के भीतर सुगम्यता सुनिश्चित करने पर ज़ोर दिया जाता है।
 - **नियामक और शिकायत नविरण तंत्र:** मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन और राज्य दिव्यांगजन आयुक्तों के कार्यालयों को नियामक प्राधिकरणों और शिकायत नविरण अभिकरणों के रूप में कार्य करने के लिये सुदृढ़ बनाना।
 - इन नकियों को अधिनियम के कार्यान्वयन की नगिरानी का कार्य सौंपा गया है।

नोट:

- RPWD अधिनियम, 2016 में 21 दिव्यांगताओं में दृष्टहीनता, अल्प दृष्टि, **कृषट रोग उपचारित व्यक्ति**, श्रवण दोष (बधरि और अल्प श्रवण क्षमता), संचलन संबंधी अक्षमता, वामनता, बौद्धिक दिव्यांगता, मानसिक रोग, ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार, **सेरेब्रल पालसी**, **मांसपेशीय दुर्विकास**, तंत्रिका संबंधी चरिकालिक रोग, **वशिष्ट अधिगम संबंधी वशिष्ट दिव्यांगताएँ (डिसिलेक्सिया)**, **मल्टीपल स्केलेरोसिस**, भाषण और भाषा संबंधी दिव्यांगता, थेलेसीमिया, हीमोफीलिया, **सकिल सेल रोग**, बधरि-दृष्टहीनता सहित बहु दिव्यांगताएँ, **एसडि अटैक पीडि** और **पार्कसिंस रोग** शामिल हैं।

दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण से संबंधित अन्य पहलें कौन-सी हैं?

- [अद्वितीय दिव्यांगता पहचान पोर्टल \(UDID\)](#)
- [दीनदयाल दिव्यांग पुनरवास योजना](#)
- [दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण एवं सहायता उपकरणों की खरीद/फटिगि की सहायता](#)
- [दिव्यांग छात्रों के लिये राष्ट्रीय फ़ैलोशिप](#)
- [दिव्य कला मेला 2023](#)
- [सुगम्य भारत अभियान](#)

दिव्यांगजनों को कनि चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?

- **दुर्गम अवसंरचना:** सार्वजनिक प्रतिष्ठानों और सेवाओं तक पहुँचने में अवसंरचना का अभाव।
 - **दिव्यांगजन सशक्तीकरण वशिग** की वर्ष 2018 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में केवल 3% भवन ही पूर्ण रूप से सुलभ थीं।
- **शैक्षिक बहिष्कार:** दिव्यांगजनों को समावेशी विद्यालयों, प्रशिक्षित शिक्षकों और सहायक प्रौद्योगिकियों के अभाव का सामना करना पड़ता है, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है।
 - वर्ष **2011 की जनगणना** के अनुसार, कुल दिव्यांग जनसंख्या की साक्षरता दर लगभग 55% है (पुरुष- 62%, महिला- 45%) तथा केवल 5% दिव्यांगजन स्नातक और उससे आगे की शिक्षा प्राप्त हैं।
- **रोजगार संबंधी चुनौतियाँ:** दिव्यांगजनों को कार्यस्थल पर भेदभाव, अपर्याप्त सुविधाओं और सामाजिक पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके आगे बढ़ने के मार्ग बाधित होते हैं।
 - यद्यपि **1.3 करोड़ दिव्यांगजन रोजगार योग्य हैं**, परन्तु केवल **34 लाख को ही रोजगार मिल पाया है।**
- **अपर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व:** वधानमंडल के तीनों स्तरों - लोकसभा, राज्य वधानमंडल और स्थानीय नकियों में दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व कम है, जिससे उनकी राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व सीमित हो गया है।

आगे की राह

- **सुगम्य अवसंरचना:** रैप, स्पर्शनीय पथ, सार्वजनिक परिवहन और अनुकूली प्रौद्योगिकियों सहित दिव्यांगता-अनुकूल सार्वजनिक अवसंरचना में सुधार करना।

- स्कूलों, अस्पतालों और डिजिटल सेवाओं के लिये सुलभता मानकों को लागू करना।
- कृत्रिम अंगों के अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना: कृत्रिम अंगों के अनुसंधान के लिये वित्तपोषण बढ़ाना तथा कृत्रिम अंगों में नवाचार के लिये राष्ट्रीय और क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करना, जिससे दवियांगजनों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके।
- पहचान और सत्यापन प्रणाली: सटीक दवियांग पहचान और प्रमाणीकरण सुनिश्चित करने के लिये बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और नयिमति ऑडिट के साथ एक केंद्रीकृत डिजिटल डेटाबेस को लागू करना।
- गगि इकोनॉमी समावेशन: दवियांगजनों के लिये लचीले, कौशल-समरूप नौकरी के अवसर प्रदान करने के लिये गगि इकोनॉमी ऐप्स के भीतर समरपति प्लेटफॉर्म बनाना।
 - सुगम्यता बढ़ाने के लिये सांकेतिक भाषा समर्थन और AI-सहायता प्राप्त कार्य मलान को शामिल करना।
- राजनीतिक आरक्षण: राज्य वधिनसभाओं और स्थानीय नकियाओं जैसे वधिनमंडलों में दवियांगजनों के लिये आरक्षण प्रणाली का प्रावधान होना चाहिये।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. सुगम्यता सुनिश्चित करने में दवियांगजन अधिकार अधनियम, 2016 की भूमिका और इसके कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न

????????

प्रश्न. भारत लाखों दवियांग व्यक्तियों का घर है। कानून के अंतर्गत उन्हें क्या लाभ उपलब्ध हैं? (2011)

1. सरकारी स्कूलों में 18 साल की उमर तक मुफ्त स्कूली शिक्षा।
2. व्यवसाय स्थापति करने के लिये भूमिका अधमिन्य आवंटन।
3. सार्वजनिक भवनों में रैंप।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

??????:

प्रश्न: क्या वकिलांग व्यक्तियों का अधिकार अधनियम, 2016 समाज में इच्छति लाभार्थियों के सशक्तीकरण और समावेशन हेतु प्रभावी तंत्र सुनिश्चित करता है? चर्चा कीजिये। (2017)